

□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□
 □□□□ □□ □□□□
 (□□.□□.□□□□□□, □□□)

पूर्ण बेंच

**एस. एस. संधवालिया सीजे, पी. सी. जैन और एस. एस. कांग,
 न्यायाधीशों के समक्ष**

सूबेदार मुंशी राम और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1976 का 8740।

2 अगस्त, 1979।

पंजाब विलेज कॉमन लॉइस (रेगुलेशन) एक्ट (1961 का 18)

(2) ए.आई.आर. 1964 पी.बी.

हरियाणा अधिनियम 1974 की धारा 2(जी), 4(3) और 13-बी द्वारा यथासंशोधित धारा 2(जी), 4(3) और 13-बी-शामलात-देह से कतिपय भूमि यों और संपत्तियों को बाहर रखने के लिए पंचायत के विरुद्ध सिविल मुकदमे- चाहे सहायक कलेक्टर को हस्तांतरित किया जाए - निषेधाज्ञा से राहत के लिए प्रार्थना की गई - क्या वाद को सिविल कोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य बनाया जाएगा।

और रूप केवल ऐसे मुकदमे जो कुछ भूमि या अन्य संपत्तियों को बाहर रखने के लिए पंचायत के खिलाफ सिविल अदालतों में दायर किए गए थे। शमीलत देह पंजाब विलेज कॉमन लॉइस (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 2 (जी) के तहत या धारा 4 (3) में उल्लिखित किसी भी आधार पर अकेले सहायक कलेक्टर को स्थानांतरित किया जा सकता है। (पैरा 3)।

यह माना गया कि यह तथ्य कि निषेधाज्ञा की राहत के लिए भी प्रार्थना की गई है, सिविल कोर्ट द्वारा इस तरह के मुकदमे को सुनवाई योग्य नहीं बनाया जाएगा यदि उक्त मुकदमा पंचायत के खिलाफ है और जिसमें इस आधार पर राहत का दावा किया गया है कि भूमि को शमीलत-देह से बाहर रखा जाए। (पैरा 3)।

(पूर्ण पीठ ने माना है कि कमल सहकारी किसान सोसाइटी लिमिटेड में इस न्यायालय के दो खंडपीठ के फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं

है बहुत। ग्राम पंचायत 1976 पी.एल.जे. 237 और दिघ राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1977 पी.एल.जे.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट पेटिडिन प्रार्थना करता है कि रिट याचिका को अनुमति दी जाए और याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित राहत दी जाए: -

- (१) मामले के रिकॉर्ड मंगाए जाएं और मामले की परिस्थितियों के अनुरूप प्रमाण पत्र या परमादेश या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करके आदेश पी-2 और पी-3 को रद्द किया जाए;
- (२) हरियाणा पर लागू पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट की धारा 13-बी को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
- (एच) कि याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक विवादित संपत्ति से बेदखल करने पर रोक लगाई जाए;
- (iv) याचिकाकर्ताओं को लागत की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से योगेश कुमार शर्मा के साथ एडवोकेट जनिंदर कुमार।

ए.एस. नेहरा, अतिरिक्त ए.जी.

अशोक अग्रवाल, एडवोकेट, उत्तरदाता 4 के लिए.

प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के लिए आई. सी. जैन, अधिवक्ता।

निर्णय

प्रेम चंद जैन, न्यायाधीश।

(1) हमारा यह निर्णय 1976 के सीडब्ल्यूपी संख्या 8740 (मुंशी राम, आदि) का निपटारा करेगा। बनाम हरियाणा राज्य, आदि। सी.डब्ल्यू.पी. 1978 का 5178 (दीवान सिंह, आदि) बनाम हरियाणा राज्य, आदि और 1977 का एसएओ नंबर 54 (तेजा, आदि) बनाम जीत राम, आदि) जैसा कि इन सभी मामलों में कानून का सामान्य प्रश्न उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त मामलों की सुनवाई के समय, याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह पेश किया गया था कि **कमल सहकारी किसान सोसाइटी लिमिटेड बनाम ग्राम पंचायत 1976, पी.एल.जे.1977, पी.एल.जे. और दिघ राम बनाम दिघ राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1976, पी.एल.जे.इस न्यायालय के दो खंडपीठ के फैसलों के बीच टकराव था।** पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन)

□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□
 □□□□ □□ □□□□
 (□□.□□. □□□□□□, □□□)

अधिनियम (1961 का 18) में 1974 के हरियाणा अधिनियम संख्या 34 द्वारा जोड़ी गई धारा 13-बी की व्याख्या के संबंध में (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)। जैसा कि स्पष्ट है, दिनांक 6 अप्रैल, 1977 के 1976 के सीडब्ल्यूपी संख्या 8740 में पीठ के आदेश से, उपर्युक्त दो खंडपीठ निर्णयों में स्पष्ट रूप से एक विरोधाभास पाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया था और इस तरह हम इस मामले को देख रहे हैं।

(2) इससे पहले कि मैं प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर ध्यान दूं, मैं कथित संघर्ष से निपटने का प्रस्ताव करता हूं जैसा कि याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा सुनवाई के समय के रूप में सामने लाने की कोशिश की गई थी।

(3) यह तर्क दिया गया था कि कमल को-अपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी के मामले में, डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा लिया गया विचार यह था कि केवल ऐसे मुकदमे जो धारा 2 (जी) के तहत या अधिनियम की धारा 4 (3) में उल्लिखित किसी भी आधार पर शमीलत-देह से कुछ भूमि या अन्य संपत्तियों को बाहर करने के लिए पंचायत के खिलाफ सिविल अदालतों में स्थापित किए गए थे, उन्हें ही स्थानांतरित किया जा सकता है। (जिसके निर्णय में मैं एक पक्ष था), यह माना गया है कि धारा 13-बी किसी भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति को शमीलत-देह से बाहर रखने के आधार पर सभी दावों का प्रावधान करती है/कमल सहकारी किसान समिति के मामले में प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नानुसार हैं: -

"इस धारा को पढ़ने से पता चलता है कि पंचायतों के खिलाफ सिविल अदालतों में लंबित मुकदमों, जिसमें इस आधार पर राहत का दावा किया गया है कि भूमि को शमीलत-देह से बाहर रखा गया है, को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। श्री आनंद द्वारा इस पर बल दिया गया है। स्वरूप, 'बहिष्कृत' और 'पंचायत के विरुद्ध' शब्दों पर, जिसे मैंने ऊपर पुनः प्रस्तुत खंड में रेखांकित किया है। यह उल्लेखनीय है कि सिविल न्यायालय से सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को हस्तांतरित करने के लिए विचार किए जाने वाले मुकदमों में दो तत्व होने चाहिए, अर्थात्, (1) यह शमीलत-देह से भूमि के बहिष्करण के लिए होना चाहिए, और (ii) यह पंचायत के खिलाफ होना चाहिए। यदि किसी वाद में उपरोक्त

सामग्री नहीं है, तो इसे सिविल कोर्ट द्वारा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यह विधियों की व्याख्या का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जहां व्याकरणिक निर्माण स्पष्ट और प्रकट है, वह निर्माण तब तक प्रबल होना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत कुछ मजबूत कारण न हो। यदि मूर्ति की भाषा स्पष्ट है, तो न्यायालय को इसे प्रभावी बनाना चाहिए, और इसे विधायिका के कथित इरादे को पूरा करने के लिए इसके संचालन का विस्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह क़ानून को उसी रूप में ले जैसा वह खड़ा है और उसके शब्दों को उसके प्राकृतिक महत्व के अनुसार माने। विधायिका के इरादे को प्रभावी किया जाना है जैसा कि क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों में व्यक्त किया गया है। उस इरादे को खोजने के लिए सहायता में कोई बाहरी विचार नहीं बुलाया जा सकता है। उपरोक्त खंड में, मेरे विचार से, विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं। उनकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि शमीलत-देह से संबंधित सभी मामले, जो सिविल कोर्ट में लंबित हैं, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। यदि विधायिका का इरादा इस आशय का होता तो इस धारा की भाषा भिन्न होती। धारा 13-ख में केवल ऐसे मुकदमे आते हैं जो धारा 2(जी) के तहत या 1961 अधिनियम की धारा 4(3) में उल्लिखित किसी भी आधार पर शामिल-देह से कतिपय भूमि या अन्य संपत्तियों को बाहर रखने के लिए पंचायत के विरुद्ध सिविल न्यायालयों में दायर किए गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा इस आशय की घोषणा के लिए स्थापित किया गया मुकदमा कि कुछ भूमि को शमीलत-देह में शामिल किया जाना चाहिए। उपरोक्त धारा के प्रावधानों के तहत नहीं आता है।

जबकि *दिघ राम के मामले* में, जिन प्रासंगिक टिप्पणियों पर हमारा ध्यान आकषत किया गया था, वे निम्नलिखित शब्दों में हैं -

इस बिंदु के तहत उठाए गए अपने तर्क के लिए समर्थन मांगने के लिए, विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया है:

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 37 (2)। यह प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम के तहत निषेधाज्ञा की राहत प्रदान नहीं की गई है और वर्तमान मामले में मुकदमा निषेधाज्ञा के लिए है, इसलिए मामले पर केवल एक सिविल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इस संबंध में **अंगनू बनाम महाबीर और एक अन्य** ए.आई.आर. 1954 All. 768 और **लुइंका वेंकटव्य बनाम आदि किशतय्या** ए.आई.आर. 1956 हैदराबाद 192. हालांकि, ये प्राधिकरण तथ्यों पर भी अलग-अलग हैं। इलाहाबाद मामले में, दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि मुकदमे के लिए मंच सिविल कोर्ट था, न कि राजस्व न्यायालय। यह माना गया था कि यदि राजस्व न्यायालय सभी राहतों को प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं था, तो मुकदमा केवल एक सिविल कोर्ट में होगा। इसी तरह, दूसरे मामले में, न्यायालय को हैदराबाद किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम के बारे में जल्ल कर लिया गया था, और यह माना गया था कि अधिनियम की धारा 99 सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रोक के रूप में काम करेगी, यदि मामला ऐसी प्रकृति का है जिसे अधिनियम में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा निपटाया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, संशोधन अधिनियम की धारा 13-बी, हालांकि, किसी भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति को शामिलत देह से बाहर रखने के आधार पर सभी दावों का प्रावधान करती है/तथ्य यह है कि निषेधाज्ञा का रंग धारा 13-बी के तहत परिकल्पित बुनियादी ढांचे पर फैला हुआ है, इससे कोई भौतिक अंतर नहीं पड़ेगा, और न ही यह सहायक कलेक्टर को विवाद का निर्धारण करने और राहत देने से बाहर करेगा। याचिकाकर्ता इस बिंदु पर भी विफल रहता है।

पूरे मामले पर सोच-समझकर विचार करने के बाद, मैं पाता हूँ कि *दिघ राम के मामले* में निर्णय, जहां तक यह अधिनियम की धारा 13-बी की व्याख्या से संबंधित है, को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ा जा रहा है, और एक काल्पनिक संघर्ष पेश करने की कोशिश की जा रही है। पीठ के समक्ष तर्क दिया गया था कि धारा 13-बी के तहत, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा राजस्व न्यायालय की क्षमता के भीतर नहीं था और सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को इस तरह के मुकदमे के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता था और यह उस बिंदु पर है कि उपरोक्त पुनः प्रस्तुत टिप्पणियां की गई थीं। उक्त टिप्पणियों से, यह नहीं हो सकता है

धारा 13-बी की व्याख्या इसलिए की गई है ताकि ग्राम पंच, आयति के खिलाफ किसी भी मुकदमे या कार्यवाही को अपने भीतर समाहित किया जा सके। *दिघ राम* के मामले में जो कहा गया है वह यह है कि यह तथ्य कि निषेधाज्ञा की राहत के लिए भी प्रार्थना की गई है, सिविल कोर्ट द्वारा इस तरह के मुकदमे को सुनवाई

योग्य नहीं बनाएगा यदि उक्त मुकदमा पंचायत के खिलाफ है और जिसमें इस आधार पर राहत का दावा किया गया है कि भूमि को *शमीलत-देह से बाहर रखा जाए*।

(4) इस मामले के इस दृष्टिकोण में, मैं मानता हूँ कि *दिघ राम* के मामले में निर्णय कमल सहकारी किसान समिति के मामले में *खंडपीठ के निर्णय के विपरीत नहीं है*, जो अधिनियम की धारा 13-बी के प्रावधान के संबंध में है।

(5) वकील जिनेंद्र कुमार ने यह भी दलील दी कि पूरी धारा 13-ए को निरस्त कर दिया गया है, धारा 13-बी का भी वही हश्र होना चाहिए जैसा धारा 13-ए की उप-धारा (5) और (7) को धारा 13-बी में अंतर्निहित किया गया है। विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था कि धारा 13-ए की उप-धारा (5) और (7) को निरस्त कर दिया गया है, जिसे धारा 13-बी में नहीं पढ़ा जा सकता है और इस स्थिति में, धारा 13-बी की उपधारा (5) या (7) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में धारा 13-बी अव्यावहारिक हो जाती है।

(6) विद्वान वकील की इस दलील पर गुण-दोष के आधार पर गौर करने की जरूरत नहीं है और *दिघ राम के मामले में फैसले और लातूर सिंह और अन्य बनाम कलेक्टर, करनाल और अन्य* 1979 पी.एल.जे. में एक अन्य हालिया खंडपीठ के फैसले को देखते हुए इसे सीधे खारिज किया जा सकता है।

(7) सामान्य प्रक्रिया में, याचिकाओं/अपीलों को गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजा जाना चाहिए था, लेकिन हमने उस मार्ग को नहीं अपनाया और गुण-दोष के आधार पर भी याचिकाओं/अपीलों पर सुनवाई करने का निर्णय लिया।

(8) अब मैं प्रत्येक मामले के गुण-दोष से अलग से निपटूंगा। *सीडब्ल्यूपी नं. 8740/1976*।

(9) इस याचिका में सूबेदार मुंशी राम और हरि सिंह ने सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर द्वारा 8 जून, 1976 को पारित आदेश और न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती दी है। कलेक्टर, रोहतक, दिनांक 6 सितम्बर, 1976 (क्रमशः अनुलग्नक पी/एल और पी/2 की प्रतियां)। मामले के स्वीकृत तथ्य यह हैं कि सितंबर, 1973 में, भोला राम, प्रतिवादी नंबर 8 ने ग्राम पंचायत, प्रतिवादी एनएलओ के समक्ष एक आवेदन दायर किया। 4 याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए मार्ग पर अतिक्रमण को हटाने के लिए। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया। लेकिन

संशोधन पर, उक्त आदेश को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झज्जर द्वारा रद्द कर दिया गया और मामले को नए निर्णय के लिए भेज दिया गया। रिमांड पर लेकर मामले की सुनवाई दूसरी पंचायत ने की। सामग्री पर विचार करने पर, ग्राम पंचायत ने खुद को मामले का फैसला करने में असमर्थ पाया और प्रतिवादी नंबर 8 को उचित अदालत में उसका इलाज करने का निर्देश दिया।

(10) इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 8 ने अतिक्रमण हटाने के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश, झज्जर की अदालत में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। मुकदमा लंबित रहने के दौरान, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट को हरियाणा में इसके आवेदन में संशोधित किया गया था और धारा 13-ए और 13-बी को पेश किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा परीक्षण के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर को स्थानांतरित कर दिया गया था। सहायक कलेक्टर ने गुण-दोष के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की और अंततः 8 जून, 1976 के अपने आदेश के तहत उसी का आदेश दिया। प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष याचिकाकर्ताओं की अपील को भी कलेक्टर द्वारा 6 सितंबर, 1976 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

(11) ऊपर वर्णित तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को स्थानांतरित किया गया मुकदमा वह था जो भोला राम, प्रतिवादी नंबर 8 द्वारा याचिकाकर्ताओं को कथित मार्ग पर कोई भी अतिक्रमण करने से रोकने के लिए दायर किया गया था। वाद पत्र में दिए गए कथनों से, यह स्पष्ट है कि भोला राम द्वारा दायर मुकदमा दो अवयवों को संतुष्ट नहीं करता है, अर्थात्, यह शमीलत देह से भूमि को बाहर करने के लिए मुकदमा नहीं था और यह ग्राम पंचायत के खिलाफ दायर नहीं किया गया था। इस स्थिति में, कानूनी रूप से मुकदमा विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को परीक्षण के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था।

(12) इस स्थिति का सामना करते हुए, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं क्योंकि जिस आदेश द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने मुकदमा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को स्थानांतरित कर दिया था, उसे याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

(13) मेरे लिए, यह आपत्ति असमर्थनीय प्रतीत होती है। अधिनियम के तहत, सहायक कलेक्टर के पास विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और इस स्थिति में, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी का आदेश अमान्य होगा। इसके अलावा, यह कहना गलत है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित स्थानांतरण के आदेश पर याचिकाकर्ताओं द्वारा सवाल नहीं उठाया गया है। याचिका में धारा 13-बी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के अलावा, यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि मुकदमे को अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत से कानूनी रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मुकदमे में, वादी द्वारा ग्राम पंचायत के खिलाफ इस आधार पर कोई राहत का दावा नहीं किया गया था कि संबंधित अचल संपत्ति को *शमीलत देह* से बाहर रखा गया था। अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत या अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित किसी अन्य आधार पर। दोनों तरफ से कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया था।

(14) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूँ, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर के दिनांक 8 जून, 1976 के आदेश और कलेक्टर, रोहतक के दिनांक 6 सितंबर, 1976 के निर्णय (क्रमशः अनुलग्नक पी/एल और पी/2 की प्रतियां) और विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश को भी रद्द करता हूँ, जिसके द्वारा मुकदमे को परीक्षण के लिए सहायक कलेक्टर को स्थानांतरित कर दिया गया था। और विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश को मामला दर्ज करने का निर्देश दें और उसके बाद कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें। मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता हूँ।

(15) पक्षकारों को उनके विद्वान वकील के माध्यम से 27 अगस्त, 1979 को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
सी. डब्ल्यू. पी. 5178/1978।

(16) दीवान सिंह और अन्य ने सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, रोहतक के 9 जून, 1978 के आदेश को रद्द करने के लिए यह याचिका दायर की है, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 13-बी के तहत याचिकाकर्ताओं के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था और अधिनियम की धारा 7 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था। आदेश पारित होने के 10 दिनों के भीतर

□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□

□□□□ □□ □□□□

(□□.□□.□□□□□□, □□□)

इसे खाली न करें।

(17) इस याचिका में, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 13-बी के तहत मुकदमा दायर किया और यह सही भी था क्योंकि याचिकाकर्ताओं का मुकदमा ग्राम पंचायत के खिलाफ था और भूमि के बहिष्कार के लिए था।

शमीलत देह जिसके स्वामित्व का दावा उन्होंने किया था। इस स्थिति में, मुकदमा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा सुनवाई योग्य था और यह उनके द्वारा सही निर्णय लिया गया था।

(18) हमारे सामने केवल एक अन्य बिंदु पर बहस की गई थी कि सहायक कलेक्टर के फैसले के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की गई है और उस स्कोर पर धारा 13-बी को असंवैधानिक के रूप में रद्द किया जाना चाहिए। ऊपरी तौर पर यह तर्क भ्रामक प्रतीत होता है। विधायिका ने यह प्रावधान नहीं किया कि धारा 13 के उप-संप्रदाय (9) के प्रावधान अधिनियम की धारा 13-बी के तहत किए गए निर्णयों पर भी लागू होंगे। अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और यदि यह कानून में प्रदान नहीं किया गया है, तो एक वादी उस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है या दलील नहीं दे सकता है कि उस आधार पर प्रावधान असंवैधानिक है।

(19) मेरे इस दृष्टिकोण को लातूर सिंह और अन्य बनाम कलेक्टर, कमल और अन्य (5 सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की नवीनतम खंडपीठ के फैसले से पूरा समर्थन मिलता है।

(20) इस याचिका में कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया था।

(21) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे इस याचिका में कोई दम नहीं दिखता है और परिणामस्वरूप इसे खारिज कर देता हूँ लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

(22) तेजा और साधु ने प्रतिवादियों को विवादित भूमि में वादी के कानूनी और शांतिपूर्ण कब्जे और स्वामित्व में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया और यह भी कहा कि ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश शून्य और अधिकार क्षेत्र से परे है। प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे का विरोध किया गया था।

□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□

(□□, □□, □□□□□□, □□□□)

प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि विवाद में प्रशंसा एक सार्वजनिक स्थान था, और सिविल कोर्ट के पास मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। दलीलों पर जो मुद्दे तय किए गए थे, उन पर पार्टियों ने सबूतों का नेतृत्व किया। ट्रायल कोर्ट ने पूरे सबूतों पर विचार करने पर वादी के दावे में कोई दम नहीं पाया और तदनुसार उनके मुकदमे को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री से व्यथित महसूस करते हुए, वादी ने अपील दायर की।

(23) अपील की सुनवाई करने वाले विद्वान जिला न्यायाधीश ने पाया कि सिविल कोर्ट के फैसले के संबंध में मुद्दा तैयार नहीं किया गया था। हालांकि, उन्होंने उस पर दलीलों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

मामले और अंततः यह माना गया कि मुकदमा सिविल कोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया गया था और मामले को कानून के अनुसार मामले का फैसला करने के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को स्थानांतरित करने के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित रिमांड के आदेश से असंतुष्ट, वर्तमान अपील दायर की गई है।

(24) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मुकदमा सिविल कोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य है और अधिनियम की धारा 13 या 13-बी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। मुझे डर है, मैं विद्वान दूत के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हूँ। स्वीकार किए गए तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं द्वारा शमीलत देह से विवाद में भूमि को बाहर करने के लिए ग्राम पंचायत के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है / अपीलकर्ता खुद को संपत्ति के मालिक होने का दावा करते हैं। इस स्थिति में, विद्वान जिला न्यायाधीश को अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लेने और मामले को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश को सौंपने में उचित ठहराया गया था।

(25) इस मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे इस अपील में कोई दम नहीं दिखता है और परिणामस्वरूप इसे खारिज कर देता हूँ, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 27 अगस्त, 1979 को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

एस.एस. संधवालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूँ।

एस. सी. के.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

अंबाला, हरियाणा